शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 22-29 जनवरी 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या प्रदेश सरकार का राममय होना चुनावी लाभ दे पायेगा?

- एक मंत्री और दो विधायकों का अयोध्या जाना किसी बड़ी राजनीति का संकेत है
- क्या ई.डी. के एजैण्डे पर हिमाचल सरकार आ गई है

शिमला/शैल। हिमाचल के सुक्खु सरकार ने राम मन्दिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। इस अवसर पर सुक्खु के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या इस आयोजन में शामिल होने भी गये थे। विधायक सुधीर शर्मा और चैतन्य शर्मा भी इस आयोजन में शामिल रहे हैं। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खु और कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और दूसरे मंत्रियों और नेताओं के जिस तर्ज में इस आयोजन पर ब्यान रहे हैं उससे लगता था कि हिमाचल की पूरी सरकार इस मौके पर अयोध्या होगी। लेकिन शायद जब केन्द्र में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस आयोजन को संघ/भाजपा का आयोजन करार देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया तब हिमाचल सरकार ने भी अपना फैसला बदला। फिर भी इस कार्यक्रम से अपने मानसिक जुड़ाव को प्रदर्शित करते हुये इस अवसर पर जो योजनाएं और कार्यक्रम घोषित कर सकते थे वह सब कुछ किया है। राज्य सरकार और उसके नेताओं के इस आचरण का विपक्षी एकता के गठबंधन ''इन्डिया'' पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पता तो आने वाले दोनों में चलेगा। कांग्रेस हाईकमान भी इस सबको कैसे लेती है यह देखना भी दिलचस्प होगा।

अभी लोकसभा के चुनाव शायद अप्रैल में होने जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के नाते कितनी सीटों पर पार्टी जीत हासिल कर पाती है यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

इस समय सुक्खु सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को हर माह एक हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज

लेना पड़ रहा है। जो सरकार विधायक विकास निधि का भुगतान विधायकों को न कर पायी हो। कुछ निगमो/बोर्डो के कर्मचारीयों को समय पर वेतन और पैन्शन का भुगतान न कर पा रही हो। जिसे पत्रकारों के मकानों का किराया पांच गुना बढ़ाना पड़ा हो। जो संशोधित वेतनमानों के बकाये का भुगतान न कर पायी हो उसके विकास संबंधी दावों और अन्य घोषणाओं पर कितना विश्वास कोई कर पायेगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इस परिदृश्य में सरकार और उसके नेताओं के आचरण को लेकर राजनीतिक अटकलें लगाया जाना स्वभाविक हो जाता है। क्योंकि केन्द्र की सरकार पर अपनी जांच एजैन्सियों ई.डी.,सी.बी.आई. और आयकर आदि के इस्तेमाल से राज्य

सरकारों में दखल देने के आरोप पहले दिन से ही लगते आये हैं। फिर संयोगवश हिमाचल सरकार के कई मंत्री और दूसरे नेता ठेकेदारी/बिल्डरों की भूमिका से ताल्लुक रखते हैं। फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से वैसे ही मनोबल गिरा हुआ है। ऊपर से सरकार के सिर पर गारंटीयों की ऐसी तलवार लटकी हुई है जिसका कोई समाधान सामने नहीं है। फिर व्यवस्था परिवर्तन के जुमले से जनता को और अंधेरे में रख पाना संभव नहीं होगा। स्थिति यहां तक पहुंच जायेगी की नेता अपनी ही जनता का सामना नहीं कर पायेंगे। चुनावों में हर दावे और योजना की सच्चाई सामने आ जायेगी।

फिर इस समय हिन्दी पट्टी में कांग्रेस के पास केवल हिमाचल की ही सरकार बची

हुई है। इस सरकार को ढोये रखना जहां कांग्रेस की आवश्यकता है तो इस गणित में सरकार को अस्थिर करना भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता है। इसके लिये ठेकेदार और बिल्डर पृष्ठभूमि के नेताओं को साधने के लिये ई.डी. से बड़ा हथियार और क्या हो सकता है। विश्लेष्कों के मुताबिक जब पत्र बम्ब संस्कृति के तहत कुछ पत्र जारी हुये थे उनसे ई.डी. के दखल की जमीन तैयार की गई थी। इसमें कुछ शीर्ष अफसरशाहों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं के सहयोग से कांग्रेस के कुछ विधायक मंत्री और दूसरे नेता केन्द्रीय एजैन्सियों के राडार पर चल रहे हैं। राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खु अभी भी राजनीतिक असन्तुलन के लग रहे आरोपों को साधने के लिये कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कर्मठ कार्यकर्त्ताओं को अभी सरकार में कोई समायोजन नहीं मिल रहा है। इसी परिदृश्य में जब मार्च में मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा तब राजनीतिक समीकरण और गड़बड़ायेंगे। अभी तक सरकार की योजनाओं को लेकर कोई सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन जब इन योजनाओं की व्यवहारिकता पर सवाल उठेंगे तब पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। इस समय यह सरकार अपने की भार से दम तोड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि चुनावों में यह आंकड़े सामने रखने होंगे कि कितने लोगों को स्थाई रोजगार मिल पाया है? कितने युवा सोलर यूनिट लगा पाये हैं? कितने युवाओं को ई-टैक्सी योजना में उपदान मिल पाया है? सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिये आम आदमी पर महंगाई का बोझ डाले बिना क्या उपाय किये हैं। कठिन वित्तिय स्थिति के चलते अपने खर्चे कितने काम किये हैं? कर्ज के खर्च का ब्योरा भी इन्हीं चुनावों में पूछा जायेगा। इसलिये माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार को लेकर अवश्य कुछ घटेगा। क्योंकि सरकार और संगठन दोनों ही मोदी सरकार पर तथा भाजपा संघ पर मौन साधे चले हुये हैं। यह मौन ही आने वाले घटनाक्रम का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।

प्रदेश में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड के निरीक्षण के उपरांत, 22-जम्मू व कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गोगना के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे।

मार्च पास्ट में सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ियां भारत स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। उद्यान विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये प्रदान किए गए। राज्यपाल ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग द्वारा आयोजित एचपी डिजिटल-इग्निशन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

जिला शिमला, सिरमौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहड़ू, बाल आश्रम टूटीकंडी के अतिरिक्त हरियाणा के उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये। पुलिस बैंड की मनमोहक प्रस्तुति भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए। जिला स्तरीय पुरस्कार महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी रामपुर, जिला शिमला और प्रभुदास क्लीनिक एवं नर्सिंग होम शिमला को दिया गया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का संदेश देते हुए गुब्बारे भी छोड़े।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य को शपथ दिलाई

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित समारोह में देव राज शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, हिमाचल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस.राणा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी.धीमान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, देव राज शर्मा के परिवार के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

युवा मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवा मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग सही जानकारी, जिम्मेदारी, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ करें क्योंकि विवेक के आधार पर मतदान करके वे नये भारत का भविष्य भी निर्धारित करेंगे। उन्होंने युवा मतदाताओं से उनके मित्रों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करने का भी आग्रह किया।

राज्यपाल शिमला के गेयटी थियेटर में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस दिवस को मनाने की परंपरा लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक और सार्थक है। उन्होंने युवा मतदाताओं को 'मतदाता फोटो पहचान पत्र' प्राप्त करने पर बधाई दी और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता के रूप में योगदान करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है।

राज्यपाल ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और जमीनी स्तर पर मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में नागरिक और पुलिस प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट देश के भविष्य की नींव रखता है इसलिए उनका प्रत्येक वोट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी होता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उत्सव भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाता है।

शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने न केवल चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है बल्कि मतदाताओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने गत विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने के लिए निर्वाचन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 55,57,924 मतदाता हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 7990 है। इनमें से कई केंद्र दुर्गम स्थानों पर हैं। दुर्गम स्थानों के लिए और कई मतदाताओं की शारीरिक स्थिति के कारण मतदान की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती का सामना करते हुए भी हमारे मतदाताओं और निर्वाचन विभाग

के संयुक्त प्रयास से मतदान प्रक्रिया निष्पक्षता और सफलता के साथ हुई हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए प्रत्येक मतदाता और राज्य चुनाव विभाग को बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय 'मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम' रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस विषय का मूल उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना और चुनाव में सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस सोच के साथ किए गए प्रयासों से जागरूकता आएगी और जब सभी लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे तो हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।

इससे पहले, राज्यपाल ने नये मतदाताओं को 'मतदाता फोटो पहचान पत्र' भी वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का पुरस्कार भी प्रदान किया तथा मतदाता शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य मतदाताओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करता है। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में राज्य में वोट प्रतिशत 75.8 था, जो अब तक का सबसे अधिक वोट प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल की सराहना की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी अधिक वोट प्रतिशतता हासिल करने के प्रयास किये जाएंगे।

इससे पहले, राज्यपाल ने नए मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक पोस्टर, गीत और वीडियो बनाने की प्रतियोगिता शुरू की जो 1 मार्च, 2024 तक चलेगी। उन्होंने 'पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0' भी लांच किया। इस अवसर पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का एक वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया।

इस अवसर पर हिमाचल के शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और निर्वाचन विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत प्रत्येक शिक्षण संस्थान में चुनावी साक्षरता सुनिश्चित की जाएगी ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मतदाता, मतदान के महत्व को समझ सकें और शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं समृद्धि की कामना की है।

अपने बधाई सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि देशवासियों के परिश्रम तथा सहयोग से राष्ट्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। गणतंत्र दिवस सभी को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों का भारत को शांतिपूर्ण और प्रगतिशील देश बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमें गणतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए निरन्तर अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने भी सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है जिसका श्रेय राज्य के मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों को जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह गर्व की बात है कि हिमाचल मुख्य क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि लोगों के सहयोग से प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने तथा देश के समृद्ध राज्यों में शामिल करने में सफल होगी।

एनएसएस स्वयंसेवियों की राज्यपाल से भेंट

शिमला/शैल। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने पहुंचे एनएसएस के स्वयंसेवियों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। प्रदेशभर के एक सौ एनएसएस स्वयंसेवी शिमला में 18 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे शिविर में भी भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य इसके आदर्श वाक्य 'स्वयं से पहले आप' में निहित है। इस विचार में परोपकार की भावना के साथ दूसरों की आवश्यकता को अपनी जरूरतों से अधिक महत्व दिया जाता है। एनएसएस युवा वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसी सामाजिक गतिविधियों से जोड़ता है। विद्यार्थियों की नैतिक शिक्षा और समग्र विकास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य कर रहे एनएसएस की मूल भावना ही सेवा है।

इस अवसर पर कैम्प कमांडर मुकेश सलारिया ने राज्यपाल का स्वागत किया और परेड कमांडर रामभज ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।

स्वयंसेवियों ने इस अवसर पर एनएसएस गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वन मित्र भर्ती के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से आरम्भ होंगे शारीरिक परीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम

सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक और तकसीम के 4000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि वर्तमान सरकार जन-जन की सरकार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यह परियोजना अनूठी होगी क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डेटा डिजिटिलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इजराइल और स्कैडेनिवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना आरम्भ की है। इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में ई-वाहनों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है। उन्होंने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि ई-वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने के पहले सप्ताह से शारीरिक परीक्षण भी आरम्भ हो जायेगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का उत्सव मनाते हुए हम अपने वीर नायकों, हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार और प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अविस्मरणीय योगदान रहा है और बर्फबारी के बीच 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश की जनता को यह सौगात देने वे स्वयं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पधारी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के साथ प्रदेश को अगले चार वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने एवं 10 सालों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

उप-मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जागरूकता वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला से रिज मैदान तक सचिवालय कर्मचारी संघ की सड़क सुरक्षा

जागरूकता वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में सचिवालय कर्मचारियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बहु आयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दृष्टिगत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं इसलिए वाहन चालकों के साथ आम आदमी को भी सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना नितांत आवश्यक है। परिवहन विभाग इसी लक्ष्य के साथ निरन्तर कार्य कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ-साथ सीसीटीवी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। वाहनों के दस्तावेज भी ऑनलाइन जांचे जा सकेंगे। विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहयोग से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए कार्य किया जा रहा है। उप-मुख्यमंत्री ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

प्रदेश में स्टार्ट-अप और नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही सरकार:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में उद्योग विभाग ने भारतीय प्रबन्धन संस्थान सिरमौर तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के साथ इन संस्थानों में नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए।

उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति ने प्रदेश सरकार की ओर से यह समझौता

ज्ञापन हस्ताक्षरित किए।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्ट अप को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान करने के दृष्टिगत नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने इन दो अग्रणी संस्थानों के साथ यह समझौता ज्ञापन किए हैं। इनके साथ ही अब प्रदेश में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबन्धन संस्थान सिरमौर नए स्टार्ट-अप को रणनीति बनाने, नेटवर्किंग और बाजार तक पहुंच से संबंधित समझ विकसित करने के साथ ही अन्य उपयुक्त सहयोग प्रदान करेगा। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश स्थित प्रमुख संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि राज्य में नए उद्योगों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि नए उद्यमी इन प्रमुख संस्थानों से अन्तरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में आए बदलाव के बारे में कई तरह के नवाचार एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर इन्हें अपने उद्यमों में उपयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह संस्थान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अपने प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। इस तरह यह पारिस्थितिकी तंत्र उद्यमियों एवं इन संस्थानों दोनों के लिए ही लाभकारी है।

उन्होंने कहा कि रोजगार प्राप्त करने के बजाय युवा रोजगार प्रदाता बन सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप/नवाचार परियोजनाएं/नव उद्योग योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्ट-अप को व्यावसायिक सलाह और समग्र रूप से संचालन संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते हुए इनकी उन्नति सुनिश्चित करना है ताकि रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकें।

उद्योग मंत्री ने कहा कि इन्क्यूबेशन सहयोग उद्यमियों को व्यापार में बढ़ावा देने तथा नए स्टार्ट-अप की सफलता में सहायक है। इन नवाचारों को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत राज्य सरकार विभिन्न संगठनों, औद्योगिक घरानों अथवा उद्योग साझेदारों के साथ मिलकर इन्क्यूबेटर स्थापित कर रही है। इससे स्टार्ट-अप संचालकों को पूंजीगत व संचालन व्यय में भी सहयोग मिल सकेगा। इस पहल के तहत इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करते हुए राज्य सरकार के सहयोग से स्टार्ट-अप को निधि जारी कर अनुदान आधार पर एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिसमें उद्योगों की भागीदारी से इस तरह के कार्यक्रमों के संचालन में गति लाई जा सके।

उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा हिमाचल को श्रेणी-ख राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग में बेस्ट परफोर्मर आंका गया है।

शिमला शहर में अधोसंरचना विकास पर व्यय होंगे 100 करोड़ रुपये

55 करोड़ रुपये से बिजली की तारें होंगी भूमिगत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन महत्व के स्थलों के सौन्दर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 55 करोड़ रुपये की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सौन्दर्यीकरण बढ़ाने के साथ-साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर के सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही से स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को लोगों की सुविधा के लिए सर्कुलर रोड से सभी बाधाओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और पर्यटकों की बढ़ती आमद के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूँदें गन्दी हैं, तो सागर गन्दा नहीं हो जाता।

..... महात्मा गाँधी

2सम्पादकीय

क्या राम मन्दिर असफलताओं को छुपाने का माध्यम बनेगा?

क्या राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक आयोजन था? क्या राम से जुड़ी आस्था का राजनीतिक करण था यह आयोजन? क्या देश के सारे राजनीतिक दल न चाहते हुये भी इसमें एक पक्ष बन गये हैं? यह और ऐसे कई सवाल आने वाले समय में उठेंगे। क्योंकि देश का संविधान अभी भी धर्मनिरपेक्षता पर केंद्रित है। यह देश बहु धर्मी और बहु भाषी है। ऐसे में सरकार का घोषित/ अघोषित समर्थन किसी एक धर्म के लिये जायज नहीं ठहराया जा सकता। राम मन्दिर आन्दोलन पर अगर नजर डाली जाये तो इस पर शुरू से लेकर आखिर तक संघ परिवार और उसके अनुषांगिक संगठनों का ही वर्चस्व रहा है। यही कारण रहा है कि आज संघ-भाजपा में ही इसके प्रणेता हाशिये पर चले गये और वर्तमान नेतृत्व इसका सर्वो सर्वा होकर भगवान विष्णु के अवतार होने के संबोधन तक पहुंच गया। इस स्थिति का संघ/भाजपा के भीतर ही क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी आने वाले दिनों में सामने आयेगा यह तय है। क्योंकि पूरा आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गिर्द केन्द्रित हो गया था। भाजपा के अन्य शीर्ष नेता इस आयोजन में या तो आये ही नहीं या उन पर कैमरे की नजर ही नहीं पडी।

राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शीर्ष धर्मगुरुओं चारों शंकराचार्यो ने यह सवाल उठाया था कि अधूरे मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसा करना कई अनिष्टों का कारण बन जाता है। शंकराचार्यो का यह प्रश्न इस आयोजन में अनुत्तरित रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह सवाल हर गांव में उठेगा। क्योंकि हर जगह मन्दिर निर्माण होते ही रहते हैं। इसी आयोजन में प्राण प्रतिष्ठा से पहले साढ़े सात करोड़ से निर्मित दशरथ दीपक का जलकर राख हो जाना क्या किसी अनिष्ट का संकेत नहीं माना जा सकता? स्वर्ण से बनाये गये दरवाजे पर उठे सवालों को कितनी देर नजरअन्दाज किया जा सकेगा? प्राण प्रतिष्ठा के बाद शीशे का न टूटना सवाल बन चुका है। आज मौसम जिस तरह की अनिष्ट सूचक होता जा रहा है क्या उसे आने वाले दिनों में अतार्किक आस्था अगर इन सवालों का प्रतिफल मानने लग जाये तो उसे कैसे रोका जा सकेगा। हिन्दू एक बहुत बड़ा समाज है जिसमें मूर्ति पूजक भी हैं और निराकार के पूजक भी हैं। राम की पूजा करने वाले भी हैं और रावण के पूजक भी हैं। आर्य समाज ने तो हिन्दू धर्म के समान्तर एक अपना समाज खड़ा कर दिया है। आर्य समाजियों के अनुसार वेद का कोई मन्त्र यह प्रमाणित नहीं करता कि मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? राधा स्वामी कितना बड़ा वर्ग है क्या उसे राम की मूर्ति की पूजा के लिये बाध्य किया जा सकता है। संविधान निर्माता डॉ. अम्बेदकर क्यों बौद्ध बने थे? ऐसे अनेकों सवाल हैं जो इस आयोजन के बाद उठेंगे उसमें हिन्दू समाज की एकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा यह देखना रोचक होगा।

इस आयोजन ने हर राजनीतिक दल और नेता को इसमें एक पक्ष लेने की बाध्यता पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही इस आयोजन के आयोजकों की सफलता रही है। इस आयोजन के बाद लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व करवाने के संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। इस चुनाव में राम मन्दिर निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को केन्द्रिय मुद्दा बनाया जायेगा। सारे सवालों को नजर अन्दाज करते हुये प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम देना प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि माना जायेगा। इस उपलब्धि के साये में देश की आर्थिकी, बेरोजगारी और महंगाई पर उठते सवालों को राम विरोध करार दिया जायेगा। जिन गैर भाजपा राज्य सरकारों ने इस आयोजन के दौरान भाजपा की तर्ज पर ही कई कार्यक्रम और आयोजन आयोजित किये हैं वह लोकसभा चुनावों में भाजपा को मात दे पाते हैं या देखना भी रोचक होगा। क्योंकि हर सरकार राम मन्दिर के आचरण में अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास करेंगे।

इस्लाम के मूल चिंतन में छुपा है पश्चिम एशिया की शांति, बस सार्थक पहल की जरूरत

गौतम चौधरी

हमास और इजराइल के बीच लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से ईरान ने अपनी भूमिका बढ़ा दी। ईरान ने इजरायल के कई सैन्य और खुफिया ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं। इससे यह साबित हो गया है कि अब ईरान प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में शामिल हो गया है। हाल के बढ़े संघर्ष की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पूरी लड़ाई को एक आतंकवादी संगठन हमास के साथ जोड़ कर देख रहा है। दअरसल, यहूदी त्योहार सुकोट के अंत के अवसर पर इजरायली यहूदी समाज जश्न में मस्त था। उसी समय पूरे देश में सायरन बजने से शांति भंग हो गई। ठीक त्योहार को लक्ष्य कर हमास के आतंकवादियों ने यहूदियों पर हमला कर दिया। यह आक्रमण बेहद तेज और तकनीक से लैस था। इस आक्रमण से पूरा इजरायली समाज हतप्रभ था।

इस पूरे अमानवीय हमले के मूल में हमास है। हमास के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक आतंकवादी समूह जो 1987 में पहली बार फिलिस्तीनी जमीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जानकार बताते हैं कि इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड में है और यह उसी की फिलिस्तीनी शाखा हैं। हमास इस्लामिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) और इजरायल के बीच समझौतों का जोरदार विरोध करता रहा है। हाल ही में हुए हमले को खतरनाक सटीकता के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें हवाई हमले, समुद्री आक्रमण और जमीनी घुसपैठ सहित विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया। इससे व्यापक विनाश हुआ और भयंकर हानि हुई। वैसे तो आमने-सामने की लड़ाई में हमास ही किरदार दिख रहा है लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। यह तब और स्पष्ट हो गया जब ईरान ने अभी हाल में इजरायली ठिकानों पर मिसाइल दागे। यह विश्व शांति के लिए खतरनाक है। वैसे हमास के हमले के बाद इजरायल ने जो किया वह भी अमानवीय ही है लेकिन इजरायल को जवाबी हमले के लिए तो हमास ने ही बाध्य किया।

यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के लिए गंभीर बन गया है। गोलीबारी में फंसी फिलिस्तीनी आबादी हमास जैसे आतंकवादी समूहों की कारवाइयों के कारण अत्यधिक पीड़ित है। एक संगठन जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और एक आतंकवादी समूह के रूप में कुख्यात है। वैश्विक समुदाय के लिए इन चरमपंथी गुटों और उन निर्दोष नागरिकों के बीच अंतर करना जरूरी है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का झूठा दावा करते हैं।

इस्लामी शिक्षा स्पष्ट रूप से मानव जीवन की पवित्रता पर जोर देती है। सच पूछिए तो हमास दुनिया का एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया है, जिसने केवल यहूदियों को ही नहीं अपितु फिलिस्तीनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। हमास ने इस्लाम के उस मूलभूत सिद्धांतों का गला घोटा है, जिसमें विश्व मानवता और शांति की बात कही गयी है। हमास ने मुसलमानों की वैश्विक धारणा को धूमिल करते हुए, इजरायलियों को भारी नुकसान पहुंचाया।

कुरान मानव जीवन के मूल्य पर जोर देता है। नुकसान पहुंचाने के बजाय जीवन को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। इस जटिलता के बीच, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुगम राजनयिक समाधान और शांति वार्ता न केवल वांछनीय हैं बल्कि आवश्यक भी हैं। फिलिस्तीनी और इजरायली, दोनों ही सुरक्षा और शांति के हकदार हैं, उन्हें चरमपंथी गुटों की कारवाइयों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। मानव जीवन की पवित्रता को कायम रखना और इस्लाम की शांतिपूर्ण शिक्षाओं का पालन करना क्षेत्र में समाधान और सह-अस्तित्व की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसका अनुसरण दोनों पक्ष को करना ही होगा।

फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के आलोक में, हमास के कार्यो की स्पष्ट रूप से निंदा होनी चाहिए। इस संगठन ने अनवरत शत्रुता से दोनों पक्षों को अथाह पीड़ा पहुंचाई है। उसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने कष्ट सहा है और सहना जारी रखा है, वे न्याय के हकदार हैं, जो शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ब्यान बेहद सारथक जान पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''वर्तमान युग शांति का है। इसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समाधान हथियारों और आतंक में नहीं बल्कि ईमानदार, शांतिपूर्ण बातचीत में निहित है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस शत्रुता को समाप्त करने के लिए तेजी से हस्तक्षेप करना चाहिए। आतंकवाद की निंदा करके, शांति की वकालत कर और यह सुनिश्चित करके कि पीड़ा के लिए जिम्मेदार लोगों को शांतिपूर्ण तरीकों से जवाबदेह ठहराया जाए। इससे हम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहां सद्भाव संघर्ष पर विजय प्राप्त करेगा। तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप सिर्फ एक आवश्यकता नहीं है। यह एक नैतिक दायित्व भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति भय, हिंसा और युद्ध के विनाशकारी परिणामों से मुक्त दुनिया में रह सके।'' इस ब्यान में सबकुछ छुपा है। इसलिए विश्व समुदाय को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही ईरान हो या कतर या फिर अन्य कोई इस्लामिक देख। वहां हिंसा बढ़ाने के बदले शांति की स्थापना के पहल करना चाहिए। इस हिंसा के बीच हमें पूरी मानवता की चिंता करनी होगी। यहां अपने निहित स्वार्थ से भी परहेज करना होगा।

देशभर में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 'वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं ज़रूर वोट करता हूं विषय के साथ मनाया गया

शिमला। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मनाया गया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनुप चंद्र पांडे, अरुण गोयल ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र बनाने के लिए नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की शानदार यात्र में, भारत निर्वाचन आयोग ने 17 संसदीय चुनावों और 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनावों के सफल संचालन में बडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि आगामी आम चुनाव 2024 में देश भर में 96 करोड़ मतदाताओं, 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारियों और 12 लाख मतदान केंद्रों के साथ, भारतीय चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन का एक प्रमाण है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक अभ्यास बनाता है। उन्होंने कहा कि मतदान में प्रौद्योगिकी का उपयोग दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जो चुनावी प्रक्रिया में प्रगति और दक्षता के प्रति हमारे देश की प्रतिबधता को दर्शाता है।

उन्होंने सुचारू और समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय पहल करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सराहना की। उन्होंने वर्तमान और पूर्व भारत निर्वाचन आयोग टीमों की भी सराहना की जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण संचालन सुनिश्चित करती हैं।

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1952 से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के साथ भारत के लोकतंत्र की लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास के पन्नों से एक पन्ना लेते हुए, श्री मेघवाल ने कहा कि भारत के निर्माताओं ने लंबे संघर्ष के बाद संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया, जिसने उस काल में नव स्वतंत्र देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। उन्होंने कहा कि कई समितियों की सिफारिशों तथा संसद की मांगों के जवाब में समय-समय पर होने वाले चुनावी सुधारों के साथ चुनावी प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग में 96 करोड़ मतदाताओं का अटूट विश्वास चुनावों के सफल संचालन के लिए नींव और प्रेरणा का स्रोत दोनों है। वर्ष 2023 में 9 राज्यों में चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण संचालन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आयोग आगामी संसदीय चुनावों में सभी हितधारकों को सभी राजनीतिक दलों के लिए सर्वोत्तम संभव अनुभव और समान अवसर देने के लिए प्रतिबध है। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि भारतीय चुनावों का उदाहरण दुनिया भर में उल्लेखनीय बने और पूरी दुनिया में भारत की चुनाव प्रणाली की छवि एक स्वर्ण मानक के रूप में और मजबूत हो।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सबसे अग्रणी भागीदार हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग पार्टियों के साथ अपने जुड़ाव को पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण भागीदारी तथा राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने में सुनिश्चित उत्तरदायित्व के तीन स्तंभों पर आधारित करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे न केवल अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करें, बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा होने के अनुभव का आनंद लें।

निर्वाचन आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने यह देखते हुए कि देश ने अपनी चुनावी यात्रा में काफी प्रगति की है, कहा कि मतदाताओं का आकार पहले आम चुनाव में 17.32 करोड़ से बढ़कर आगामी आम चुनाव में संतुलित लैंगिक वितरण के साथ 96 करोड़ हो गया है। उन्होंने देश में चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबधता के लिए पुरस्कार विजेताओं सहित चुनाव मशीनरी की सराहना की।

निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति आयोग के लिए ताकत का स्रोत थी। दर्शकों में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रमुखों का जिक्र करते हुए, गोयल ने चुनावी प्रणाली के मानदंडों और मानकों का स्वेच्छा से पालन करने के लिए राजनीतिक दलों की सराहना की। भारत को न केवल सबसे बड़ा, बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र बताते हुए, गोयल ने कहा कि वर्ष 1950 के बाद से, चुनावी कदमों को रहस्यमय बनाने और सरल प्रशासनिक रूप से प्रबंधनीय एवं सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य प्रक्रियाओं को बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका किंवदंतियों में है। उन्होंने कहा कि प्रेरक को बनाए रखना और जबरदस्ती का विरोध करना भारत निर्वाचन आयोग के लोकाचार तथा उसके सफलता मंत्र की पहचान रही है। कार्यक्रम के दौरान, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए। आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभता सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2023 के दौरान चुनाव के संचालन में चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में योगदान और मीडिया द्वारा पहुंच के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 16 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2023 में चुनावों के सुचारू संचालन के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय सीईओ छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ब्रोशर और पुरस्कार विजेताओं की सूची के लिए डाउनलोड लिंक(https://www.eci.gov.in/eci-publication) 2024 के संसदीय चुनावों के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की राष्ट्र की सेवा के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग के प्रकाशन की पहली प्रति संसदीय चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा माननीय राष्ट्रपति को भेंट की गई। यह पुस्तक चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और भागीदारीपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई पहलों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राज कुमार हिरानी के सहयोग से निर्मित एक लघु फिल्म- माई वोट माई ड्यूटी भी जारी की गई। लघु फिल्म में कई मशहूर हस्तियों को लोकतंत्र की भावना और एक वोट की शक्ति को जगाने के लिए उनके संदेशों के साथ दिखाया गया है। यह फिल्म देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए https://www.youtub/nL4wZO2o-fs

समारोह के दौरान, दिल्ली के पांच नए नामांकित मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया और माननीय राष्ट्रपति द्वारा उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी सौंपे गए।

इस अवसर पर आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए एक मल्टी-मीडिया अभियान के लिए एक प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन भी जारी की गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में भारतीय चुनावों की विशेषता, चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए किए गए चुनावी सुधार, तकनीकी प्रगति और चुनाव प्रबंधन नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए इस वर्ष का विषय, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं आम चुनाव 2024 के लिए पिछले वर्ष के विषय की निरंतरता है। यह उनके वोट की शक्ति से सुसज्जित चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति मतदाताओं की आकांक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कुछ देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय नायक और बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022 जारी किया

शिमला। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021- 2022 जारी किया। मंत्रालय 2011 से एआईएसएचई का संचालन कर रहा है। इसमें एआईएसएचई के साथ पंजीकृत देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को शामिल करते हुए विभिन्न मापदंडों जैसे छात्र नामांकन, शिक्षक, बुनियादी ढांचागत जानकारी आदि पर विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।

सर्वेक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

छात्र नामांकन

उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। 2014-15 में नामांकन में 3.42 करोड़ था। इसमें लगभग 91 लाख (26.5%) की वृद्धि हुई है।

महिला नामांकन 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। 2014-15 में महिला नामांकन में 1.57 करोड़ से लगभग 50 लाख (32%) की वृद्धि हुई है।

2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में 2021-22 में एससी छात्रें का नामांकन 66.23 लाख है (44% की वृद्धि)।

एससी महिला छात्रों का नामांकन 2014-15 में 21.02 लाख था। यह 2020-21 में 29.01 लाख हुआ जो 2021-22 में बढ़कर 31.71 लाख हो गया है। 2014-15 से इसमें 51% की बढ़ोतरी हुई है।

एसटी छात्रों का नामांकन 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गया है (65.2% की वृद्धि)

एसटी महिला छात्रों के मामले में 2014-15 में नामांकन 7.47 लाख था जो 2020-21 में 12.21 लाख हो गया। 2021-22 में बढ़कर यह 13.46 लाख हो गया है। 2014-15 से इसमें 80% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ओबीसी छात्रों का नामांकन भी 2014-15 में 1.13 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 1.63 करोड़ हो गया है। 2014-15 के बाद से ओबीसी छात्र नामांकन में लगभग 50.8 लाख (45%) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ओबीसी महिला छात्रों के मामले में2014-15 में नामांकन 52.36 लाख से बढ़कर 2021-22 में 78.19 लाख हो गया है। 2014-15 से ओबीसी महिला छात्र नामांकन में 49.3% की कुल वृद्धि हुई है।

अल्पसंख्यक छात्र नामांकन 2014-15 में 21.8 लाख से बढ़कर 2021-22 में 30.1 लाख (38% की वृद्धि) हो गया है। महिला अल्पसंख्यक छात्र नामांकन 2014-15 में 10.7 लाख से बढ़कर 2021-22 में 15.2 लाख (42.3% वृद्धि) हो गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में कुल छात्र नामांकन 2014-15 में 9.36 लाख की तुलना में 2021-22 में 12.02 लाख है। पूर्वोत्तर राज्यो में 2021-22 में महिला नामांकन 6.07 लाख है, जो पुरुष नामांकन 5.95 लाख से अधिक है।

जीईआर 2014-15 में 23.7 से बढ़कर 2021-22 में 28.4 हो गया, 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए 2011 जनसंख्या अनुमान के अनुसार,। महिला जीईआर 2014-15 में 22.9 से बढ़कर 2021-22 में 28.5 हो गया है।

एससी छात्रों का जीईआर 2014-15 में 18.9 से बढ़कर 2021-22 में 25.9 हो गया है जबकि महिला एससी छात्रों का जीईआर 2014-15 में 18.1 से बढ़कर 2021-22 में 26 हो गया है।

एसटी छात्रों का जीईआर 2014-15 में 13.5 से बढ़कर 2021-22 में 21.2 हो गया है। महिला एसटी छात्रों का जीईआर 2014-15 के 12.2 से बढ़कर 2021-22 में 20.9 हो गया है।

महिला एसटी छात्रों का रिजल्ट 2014-15 में 12.2 से बढ़कर 2021-22 में 20.9 हो गया है। 2017-18 से जीपीआई लगातार 1 से ऊपर बनी हुई है यानी लगातार पांचवें साल महिला जीईआर पुरुष जीईआर से अधिक बनी हुई है।

एआईएसएचई 2021-22 के अनुसार कुल छात्रों में से लगभग 78.9% स्नातक स्तर के पाठयक्रमों में नामांकित हैं और 12.1% स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों में नामांकित हैं।

एआईएसएचई 2021-22 में स्नातक स्तर पर विषयों में कला में नामांकन (34.2%) सबसे अधिक है। इसके बाद विज्ञान (14.8%), वाणिज्य (13.3%) और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (11.8%) का स्थान आता है।

एआईएसएचई 2021-22 में स्नातकोत्तर स्तर में अधिकतम छात्र सामाजिक विज्ञान (21.1%) में नामांकित हैं। इसके बाद विज्ञान (14.7%) का स्थान आता है।

पीएचडी नामांकन 2014-15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021-22 में बढ़कर 2.12 लाख (81.2%) हो गया है।

महिला पीएचडी नामांकन 2014-15 में 0.48 लाख से दोगुना होकर 2021-22 में 0.99 लाख हो गया है। महिला पीएचडी नामांकन में 2014-15 से 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक वृद्धि 10.4% है।

2021-22 में यूजी, पीजी, पीएचडी और एम.फिल स्तरों पर कुल नामांकन में से 57.2 लाख छात्र साइंस स्ट्रीम में नामांकित हैं, जिसमें महिला छात्रों (29.8 लाख) की संख्या पुरुष छात्रों (27.4 लाख) से अधिक है।

सरकारी विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों का 58.6% हैं, जो कुल नामांकन में 73.7% योगदान करते हैं, निजी विश्वविद्यालय कुल नामांकन में 26.3% योगदान देते हैं।

2021-22 में यूजी, पीजी, एम. फिल और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 98.5 लाख है, जबकि 2020-21 में यह 94.7 लाख थी।

2020-21 में 95.4 लाख के मुकाबले 2021-22 में पास-आउट की कुल संख्या बढ़कर 1.07 करोड़ हो गई है।

2021-22 में विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता:

पुस्तकालय (99%)

प्रयोगशालाएं (88%)

कंप्यूटर केंद्र (93%)

कौशल विकास केंद्र (71%)

खेल मैदान (91%)

संस्थानों की संख्या

पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या 1,168 हैं, कॉलेजों की संख्या 45,473 और स्वायत्त (स्टैंडअलोन) संस्थानों की संख्या 12,002 है।

2014-15 से कुल मिलाकर 341 विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं।

17 विश्वविद्यालय (जिनमें से 14 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं) और 4,470 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

फैकल्टी (संकाय)

2021-22 में फैकल्टी/शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है। इनमें से लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएं हैं।

महिला फैकल्टी/शिक्षकों की संख्या 2014-15 में 5.69 लाख से बढ़कर 2021-22 में 6.94 लाख हो गई है। (2014-15 से 22% की वृद्धि) प्रति 100 पुरुष संकाय में महिलाओं की संख्या में मामूली सुधार हुआ है, जो 2020-21 में 75 से बढ़कर 2021-22 में 77 हो गया है।

राज्यपाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की में विद्यार्थियों के साथ देखा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला में अर्की स्थित शहीद कैप्टन विजयंत थापर

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से परीक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये मार्गदर्शन को सदैव याद रखने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा प्रदान करेगा। उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिए तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि आत्मविश्वास एवं इच्छाशक्ति से ही जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है और छात्रों को हमेशा धैर्य व साहस से काम लेना चाहिए। उन्होंने छात्रों से प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और सोशल मीडिया को अपनी दिनचर्या में अत्याधिक प्रभावी नहीं होने देने का आग्रह किया। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों के साथ सकारात्मक विषयों पर चर्चा करें तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

शुक्ल ने कहा कि सतत परिश्रम और आत्मविश्वास ही युवाओं के जीवन में उत्साह और उमंग पैदा करता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड के दौरान उचित शोध ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके प्रश्नों के समाधान प्राप्त हुए होंगे।

चार हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर, किन्नौर जिला के रिकांगपिओ तथा चंबा जिला के चंबा में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट के निर्माण से जहां पर्यटकों के आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को अपातकालीन स्थितियों में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी व जल विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी का मुख्य आधार है तथा पर्यटन व्यवसाय से हजारों परिवार जुड़े हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश में पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर एवं यादगार बनाया जा सकेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में वर्ष में 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला में पहली बार विंटर कॉर्निवल तथा जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन इन्हीं में से एक है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्राधिकरण ने नए उद्यमियों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के

विस्तार के लिए लगभग 1937 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की 27 प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। सरकार का यह प्रयास राज्य को निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करता है जिससे लगभग 2 हजार 715 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

नए प्रस्तावों में प्राधिकरण द्वारा जिला सोलन की नालागढ़ तहसील में टेबलेट, कैप्सूल आदि के निर्माण के लिए मैसर्स जिनोन प्राइवेट लिमिटेड आई.ए. प्लासरा को, मास्टर मैसर्स फार्मूलेशन सी.ई.ओ. आई.ए. प्लासरा तहसील नालागढ़ जिला सोलन को टेबलेट, कैप्सूल, ओइनटमेंट आदि के निर्माण के लिए, मैसर्स गौतमी एक्वाकेम प्राइवेट लिमिटेड मोहल जतपुर तहसील महतपुर जिला ऊना को सोडियम क्लोराइड एन.ए.सी.आई.ओ. के लिए, मैसर्स जे. एप्पल सी.ए. स्टोर चिड़गांव रोहडू जिला शिमला को कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए मैसर्स धीर रोसिन एंड टरपेंटाइन फैक्टरी आई. ए. टाहलीवाला, तहसील हरोली को रोसिन और तारपीन तेल के लिए, मैसर्स हिम दीप एलक्लीज केमिकल विलेज व पिओ धमांदरी जिला ऊना को कास्टिक सोडा लिक्विड, हाइड्रोजन, क्लोरीन के बनाने के लिए, मैसर्स एग्रोफार्म वैंचर्स प्राईवेट लिमिटेड गांव नरचौत, तहसील ठियोग जिला शिमला को कोल्ड स्टोर निर्मित करने, मैसर्स स्कॉटिल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड विलेज खेरी, कालाअम्ब तहसील नाहन जिला सिरमौर को ड्राई इजेक्शन, आई ड्रोप्स तैयार करने, मैसर्स महालक्ष्मी स्पीनटैक्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 4 ग्रांव मानपुरा तहसील बद्दी जिला सोलन को पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर और पॉलिस्टर चिप के निर्माण के लिए और मैसर्स भविष्य इनोवेशन, आई.ए. मझौली जिला सोलन को कोरूगेटिड बॉक्स और मोनो कार्टन इत्यादि के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तार प्रस्तावों में मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड आई. ए. कथा तहसील बद्दी जिला सोलन को शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर तैयार करने, मैसर्स लॉरियल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड झाड़माझरी, तहसील बद्दी जिला सोलन को हेयर कलर, मेडिकेटिड टॉयलेट सोप तैयार करने के लिए, मैसर्स केग इंडस्ट्रीज गांव मोगीनंद तहसील नाहन जिला सिरमौर को मॉल्टिड मिल्क फूड, आयुर्वेदिक हैल्थ स्पलीमेंट इत्यादि, मैसर्स फरमेंटा बायोटेक लिमिटेड, गांव टकोली पोस्ट ऑफिस नगर्वाइं जिला मंडी को पेनिसिलिन जी एमीडेज़ बायोकैटलिस्ट, डीएचसी, विटामिन डी-3 निर्मित करने, मैसर्स मेराकी एंटरप्राइजेज, गांव निहाल खेड़ा तहसील नालागढ़ जिला सोलन को एल्यूमिनियन के रोलिंग कोटिंग लेमिनेशन तैयार करने, मैसर्स पार्कसन्स पैकेजिंग लिमिटेड एच.पी.एस.आई.डी. सी. औद्योगिक क्षेत्र तहसील बद्दी जिला सोलन को कोरूगेटिड बॉक्सीज, मोनोकार्टन तैयार करने, मैसर्स डॉक्टर रेड्डीस लेबोरेट्रीस लिमिटेड एफ.टी. ओ-12 गांव कुंझाल तहसील बद्दी जिला सोलन को टैबलेटस, कैप्सूल, क्रीम, जैल, कॉस्मेस्टूकल इत्यादि तैयार करने, मैसर्स प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड गांव बटेट, बरोटीवाला, जिला सोलन को एम. एस. बिलेट, टीएमटी बार राउंड एंगल चौनल एम.एस. फ्लैट अदर आयरन प्रोडक्टस, एम.एस. पाइप तैयार करने, मैसर्स मोडेलेज इंडिया फूडस प्राइवेट लिमिटेड, गांव संधोली जिला सोलन को फाइफ स्टार, मोलडिड चॉकलेट, क्रमब, जेम्स तैयार करने, मैसर्स फ्रेंडस अलॉयज गांव बटेड तहसील बद्दी जिला सोलन को एम.एस.एंगल और बिलेटस के निर्माण के लिए मैसर्स, एम.टी.ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड गांव बरोटीवाला, तहसील बद्दी जिला सोलन को ऑटो कम्पोनेंटस के निर्माण के लिए, मैसर्स 3 जनरेशनस, विलेज थाना, तहसील बद्दी जिला सोलन को प्लास्टिक ऑटो अक्सेसरीज के निर्माण के लिए, मैसर्स एन.पी.पी. प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग गांव मालपुर, तहसील बद्दी जिला सोलन को मोनोकार्टन, इंसर्ट के निर्माण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान पॉलीफेब, औद्योगिक क्षेत्र दावनी तहसील बद्दी जिला सोलन को इंजेक्शन, इन्फ्यूजन- IV फ्लूइड्स इत्यादि तैयार करने के लिए, मैसर्स ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड गांव मालपुर, तहसील बद्दी जिला सोलन को इंवर्टस यूपीएस, ट्रांसफोर्मर्स, पी. सी.बी.ए., सोलर प्रोडक्टस, बैटरी असेम्बली के निर्माण के लिए, मैसर्स ग्राइंडवैल नॉटर्न लिमिटेड, गांव बटेड, बरोटीवाला, सब-डिविजन बद्दी जिला सोलन को बांडेड एब्रेसिव्स, कोडेड एब्रेसिव्स आदि के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

शिक्षा में सुधार के लिए किया 300 करोड़ बजट का प्रावधान: सीएम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान 62 जन समस्याएं प्राप्त हुई तथा 24 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाये गये, जबकि 13 इंतकाल भी सत्यापित किये गये।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अंब में दो दिवसीय चिंतपूर्णी महोत्सव, अंब में मिनी सचिवालय के निर्माण, स्वां तटीकरण के लिए 10 करोड़ प्रदान करने, पंजोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नैहरियां आईटीआई में रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोई और दियाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने तथा इस क्षेत्र में 50 पुराने टयूबवेल की मरम्मत करने के लिए तीन करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है और एक वर्ष के भीतर स्कूल का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पाठ्क्रम आरम्भ किया जा रहा है तथा छह साल का बच्चा ही पहली कक्षा में जाएगा ताकि वह तनाव महसूस न करे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक वर्ष पूर्व जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बजट का 17 प्रतिशत ही हम विकास कार्यों पर खर्च करते हैं, जबकि 83 प्रतिशत बजट अन्य कार्यों पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि 16 हजार करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों का वेतन और 10 हजार करोड़ रुपये पेंशन प्रदान करने पर खर्च होता है, जबकि प्रदेश का बजट 54 हजार करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास शुरू किए गए हैं और इसी को व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया गया है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय लागू कर रही है जिसमें सरकार को सफलता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह, पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है, जिसके लिए सरकार ने किसानों से दूध खरीद का मूल्य छह रुपए बढ़ाया है और आने वाले समय में पशु पालकों को निश्चित आय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

विधायक सुदर्शन बबलू ने आपदा के दौरान चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए 150 मकानों को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए सभी शिलान्यास व उद्घाटनों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में कुल 33.21 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए। उन्होंने 12.81 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ज्वार-नारी वाया बिल्लां दा सड़क तथा 10.90 करोड़ रुपये की लागत से अंब कस्बे के लिए पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी तथा 8.47 करोड़ रुपये की लागत से नैहरियां में बने आईटीआई भवन का लोकार्पण किया।

उप-मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की

महिला चालकों के साथ सड़क सुरक्षा पर संवाद किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह कार्यशाला आयोजित की गई।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं आज स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में लगभग एक लाख 10 हजार से ज्यादा महिला वाहन चालक हैं। महिलाएं इस तरह के जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकती हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से प्रदेशभर में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष-2024 परिवहन के क्षेत्र में सुधारों का वर्ष होगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर चर्चा कर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व योजनाएं बनाई गई हैं। विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने के प्रयासों के साथ-साथ प्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने के लिए भी कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला वाहन चालकों से संवाद करना और उनके सुझावों के अनुरूप व्यवस्था में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि यातायात विनियमन की नवीनतम प्रणाली स्थापित करने के लिए पुलिस विभाग के साथ कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ परिवहन विभाग को 15 इंटरसेप्टर प्रदान किए जाएंगे।

विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित साहित्य और अन्य सामग्री तैयार की गई है।

निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को शामिल किया गया है।

महिला वाहन चालकों ने कार्यशाला के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। चौपाल के नेरवा की रहने वाली काजल मोक्टा ने कहा कि वह सभी प्रकार के वाहन चला लेती हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं और उन्हें इस तरह के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी आगे आना चाहिए। शिमला में टैक्सी चालक भावना ने कहा कि वह लगभग 16 वर्षों से वाहन चला रही हैं और सदैव यह प्रयास रहता है कि अपने सहयोगियों के साथ-साथ आम लोगों को भी यातायात नियमों की अनुपालना के लिए जागरूक किया जाए।

कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में डिवाइन विज़डम स्कूल माजरा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों की योग्यता और रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरियां सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा अधिक है, इसलिए यह सोचने की जरूरत है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले कैसे बनें।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि में चल रहा नशे का कारोबार

कहा कि हमें बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए।

शुक्ल ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कार भी उन लोगों को प्रदान किए गये जो पेड़ों की रक्षा और लोगों की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों में टेलीविजन और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की और माता-पिता से अपने बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धा की दौड़ में चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अकेले पुलिस प्रशासन नशे को समाप्त नहीं कर सकता, इसके लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूत है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किये।

डिवाइन विज़डम स्कूल के अध्यक्ष नीरज गोयल ने राज्यपाल का स्वागत किया। डिवाइन विज़डम स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी मल्होत्रा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत व उन्नयन के लिए 152 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करेगा मंत्रालय

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन जयराम गडकरी से भेंट की

और हिमाचल में गत वर्ष भारी बारिश व भू-स्खलन के कारण हुए नुकसान सम्बंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत व उन्नयन के लिए 152 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गत वर्ष बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई भारी तबाही के पश्चात् केन्द्रीय मंत्री ने कुल्लू व मनाली का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान का जायजा लिया था। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाले राज्य सम्पर्क मार्गों के एक किलोमीटर भाग तक बहाली की घोषणा की थी। इसके पश्चात केन्द्रीय मंत्रालय को राज्य की ओर से इन सड़कों के लिए 152 करोड़ रुपये की निधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चार मुख्य राज्य मार्गों और राजमार्गों की बहाली के लिए 23.08 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन भी भेजा गया था।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस प्राक्कलन में थलौट उपमण्डल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-003 और राष्ट्रीय राजमार्ग-305 को जोड़ने वाले मार्गों की मरम्मत व रख-रखाव कार्य, मण्डी-पण्डोह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में पण्डोह से चैलचौक तक यातायात के सुचारू संचालन के लिए चैल-गोहर-पण्डोह सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण, फोरलेन कार्य के फलस्वरूप पण्डोह बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग के टकोली कुल्लू भाग की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा मण्डी-कमांद-कटौला-बजौरा मार्ग की तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है। यह सड़कें आपात स्थिति में आवश्यक खाद्य सामग्री सहित आपूर्ति श्रृंखला को बनाये रखने तथा यात्रियों के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टिक्कर-जड़ोल-गाहन-ननखड़ी-खमाड़ी सड़क के स्तरोन्नयन के लिए भी 108.33 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजी गई है जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहमति जताई। यह सड़क कोटगढ़, कुमारसैन, ननखड़ी और रामपुर तहसील की 12 पंचायतों की सेब बाहुल्य आबादी के लिए आवागमन एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है।

केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न प्राक्कलन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 152 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का भी आश्वासन दिया।

केंद्र के प्रोजेक्टों को रोकने का काम कर रही प्रदेश सरकार:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा हिमाचल मीडिया के प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक ब्यान में कहा कि भाजपा का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कांगड़ा जिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिये देहरा और धर्मशाला दोनों जगह जमीन देखी गई और निर्णय हुआ कि दोनों जगह अलग-अलग कैंपस बनेंगे। भाजपा की सरकार के समय जमीन तय हुई और जमीन की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामले आगे बढ़े। जो विश्वविद्यालय का कैंपस देहरा में बनना था, उस जमीन की कीमत और फॉरेस्ट ने पेड़ों की कीमत थी वह उस समय भाजपा की सरकार ने अदा कि और उसके बाद देहरा में कैंपस का कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास उस समय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था और साथ ही धर्मशाला में जो कैंपस बनना है, उसका भी शिलान्यास हो गया था। उसकी जमीन के फॉरेस्ट क्लीयरेंस का मामला चल रहा था और पिछले साल से वह केंद्र के वन विभाग ने प्रदेश सरकार से उस कैंपस में वन विभाग की जमीन और उसके पेड़ों की कीमत 30 करोड़ की अदायगी करने के लिए कहा था। 1 जुलाई 2023 को यह आवेदन केंद्र सरकार का आया था परन्तु प्रदेश सरकार ने इतना समय बीत जाने के बाद भी जो 30 करोड़ की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की थी वह जमा नहीं करवाई, जिसके कारण वन विभाग की एनओसी मिल नहीं रही और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने ब्यान में वर्तमान प्रदेश सरकार से भाजपा की मांग है कि प्रदेश सरकार के 30 करोड़ जो अदायगी है वह तुरंत जमा कराये। ताकि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्य को शुरू किया जा सके।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपये की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30 प्रतिशत बनने वाला सीयू का नार्थ जोन कैंपस लटक गया है। यह साफ दिखता है कि कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट को रोकने का पूर्ण प्रयास कर रही है।

जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिली चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70 फीसदी कैंपस का निर्माण कार्य जोरों-शोरों से चला है। वर्ष 2009 में स्वीकृत हुए प्रोजेक्ट को 510 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। दोनों कैंपसों के निर्माण को 476 करोड़ रुपये के टेंडर तक बुलाए हैं। इसके चलते देहरा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन जदरांगल के लिए 30 करोड़ की दरकार है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले 30 प्रतिशत निर्माण का कार्य मात्र इस कारण रुका हुआ है कि प्रदेश सरकार को केंद्रीय वन मंत्रालय सहित कुछ अन्य विभागों के पास करीब 30 करोड़ रुपये जमा नहीं करवा रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या यह लोस चुनाव प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के भाईचारे का टेस्ट होंगे?

शिमला/शैल। विधानसभा बजट सत्र 14 फरवरी से होने जा रहा है। पिछले वर्ष यह बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हुआ था। बजट सत्र का एक माह पहले ही बुला लिया जाना निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों का समय से पहले होने का स्पष्ट संकेत है। स्पष्ट है कि जब चुनाव पहले होंगे तो आचार संहिता भी पहले ही लग जायेगी। आचार संहिता पहले लगने से सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटीयों के अमल पर कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठा पायेगी। भाजपा इन गारंटीयों पर सरकार से सवाल पूछने के लिये स्वतंत्र रहेगी। वैसे भाजपा और सरकार के रिश्ते बहुत सारे मुद्दों पर आपसी भाईचारे जैसे ही हैं। क्योंकि भाजपा जब सत्ता में थी तो उसने भाजपा द्वारा ही तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने ही सौंपे आरोप पत्रों पर कोई जांच नहीं बैठायी थी। अब उसी रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाते हुये सुक्खु सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भाजपा काल के प्रशासन को न केवल यथास्थिति बनाये रखा बल्कि उसे उचित पुरस्कार भी दिया। चुनावों के दौरान सार्वजनिक रूप से जारी किये गये अपने ही आरोप पत्र पर कोई जांच बिठाने का जोखिम नहीं उठाया। पांच सौ से अधिक संस्थाओं को बन्द करके तथा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करके ठोस मुद्दे भी उपलब्ध करवाये हैं। इन दोनों को भाजपा ने उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया है।

इसी के साथ भाजपा पर जो आरोप प्रदेश को कर्ज में डूबाने का कांग्रेस लगाती थी उसमें अपने ही कर्ज के आंकड़े से पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। पीछे बरसात में आयी आपदा में केन्द्र द्वारा प्रदेश की उचित सहायता न करने के आरोपों को अब राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सरकार के राम मय होने के आचरण ने पीछे धकेल दिया है। सरकार ने विधायकों को मिलने वाली विधायक विकास निधि का आवंटन वित्तीय कारणों से रोक रखा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव समय से पहले होने के संकेत आये और भाजपा ने इस निधि को जारी करने के लिये समय की रेखा भी खींच दी तो सरकार ने यह राशि तुरन्त प्रभाव से जारी कर दी। आपसी भाईचारे और सहयोग के इससे अच्छे उदाहरण और क्या हो सकते हैं।

यह सब इसलिये प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय किसानी/बागवानी से जुड़ी सारी योजनाएं फील्ड में व्यावहारिक रूप से दम तोड़ चुकी हैं। मनरेगा में पिछले नौ माह से सरकार सामान की खरीद के लिए कोई पैसा जारी नहीं कर पायी है। गांव में मनरेगा के तहत बनने वाले 'गौ शैड' के लिये कोई पैसा जारी नहीं कर पायी है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में तो विधायक की अपनी पंचायत और अपने ही गांव के कई लोग इस सहायता की ''इन्तजार'' में बैठे हुये हैं। बागवानी से जुड़ी सारी योजनाएं दम तोड़ चुकी है क्योंकि इनके लिये न केन्द्र और न ही राज्य की मद से पैसा जारी हो पा रहा है। इसलिए इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों मौन साधे बैठे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली स्थिति तो यह है कि केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ''खाता एक नजर में'' जारी रिपोर्ट के अनुसार इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षो में 105543.71 करोड़ रुपया लैप्स कर दिया गया है। यह पैसा लाभार्थियों को जारी ही नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान सम्मान निधि के तहत जारी 6000 वार्षिक पाने वालों का आंकड़ा भी प्रश्निंत हो जाता है। कृषि मंत्रालय की यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के दावों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है। इस रिपोर्ट पर भाजपा की चुप्पी तो समझ आ सकती है लेकिन कांग्रेस के चुप रहने को भाईचारे की संज्ञा न देकर और क्या नाम दिया जा सकता है। ऐसे भाईचारे के परिदृश्य में चुनाव परिणाम क्या रहेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

घातक होगा कर्मचारीयों पैन्शनरों और बेरोजगारों में बढ़ता रोष

- कर्मचारी मांगों के परिदृश्य में सरकार की फिजूल खर्ची बनने लगी मुद्दा
- 6% ब्याज सहित बकाये के भुगतान के फैसलों की अपील करेगी सरकार

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार इस वर्ष पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों और पैन्शनरों को कोई भी आर्थिक लाभ देने की घोषणा नहीं कर पायी है। इससे कर्मचारियों और पैन्शनरों में स्वभाविक रूप से रोष पनपना नाजायज नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि सरकार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसा करने से रोक रही है तो उसे उसी अनुपात में अपने अनुत्पादक खर्चो पर रोक लगाने से शुरुआत करनी होगी। सरकारी अफसरशाही की सचिवालय में इतनी बड़ी संख्या में उपलब्धता के बावजूद एक दर्जन से अधिक सलाहकारों और विशेष कार्यधिकारियों की फौज खड़ी कर लेना अब हर आदमी को चुभने लग गया है। इसकी आवश्यकता मुख्यमंत्री को अपने विशेष कारणों से तो हो सकती है लेकिन शायद प्रदेश की जनता को नहीं है। यही स्थिति मुख्य संसदीय सचिवों की है। इन सारी नियुक्तियों के आईने में कठिन वित्तीय स्थिति का तर्क किसी के भी गले नहीं उतर रहा है।

इस समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग कर दिये जाने से प्रभावित हुये बेरोजगार युवा धरने प्रदर्शन पर आ गये हैं। संस्कृत और संस्कृति संरक्षण के बैनर तले युवा आक्रोश रैली निकाल चुके हैं। डॉक्टर एन.पी. एस. की मांग को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन में लगे हुये हैं। सरकार अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर पायी है। यह अपनी मांगों को लेकर कभी सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसा होने पर स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पडना स्वभाविक है। अब सचिवालय एवं अन्य संवद्ध पैन्शनर वैल्फेयर संगठन के प्रधान मदन लाल शर्मा और उप प्रधान भूपराम वर्मा ने एक वक्तव्य जारी करके आन्दोलन की चेतावनी दी है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 अगस्त एवं दिवाली पर प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन किस्ते 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ जारी नहीं की है। इसी के साथ संशोधित वेतनमानों का बकाया 1-1-2016 से 31-12-2021 तक जारी नहीं किया है। जबकि 2022 के बाद सेवानिवृत हुये कर्मचारियों को यह दिया जा चुका है।

इन लोगों ने मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिये इस ब्यान की निंदा की है जिसमें कहा गया था कि यह भुगतान दो वर्ष बाद 2026 में होगा। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कोषागार को निर्देश दिये हैं कि जिन केसों में उच्च न्यायालय ने 6 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाये के भुगतान के आदेश किये हैं वह भुगतान न करके इसकी अपील की जाये। सरकार के इस फरमान पर कर्मचारियों ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने के फैसले और सरकार द्वारा अब तक 13000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने पर भी गंभीर सवाल उठाये हैं। लोकसभा चुनावों से पहले उभरती यह तस्वीर सरकार के लिये घातक मानी जा रही है।